30-05-2022

वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022

समाचार पत्रों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने एक आसन्न संकट के बारे में चेतावनी जारी की है: जलवायु परिवर्तन ने मानवता के लिए एक कोड रेड शुरू कर दिया है, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यह दुविधा खाद्य प्रणालियों से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।

त्वरित मुद्दा?

- जलवायु परिवर्तन ने पहले ही कई देशों में कृषि उत्पादन को कम करना और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना शुरू कर दिया है, विशेष रूप से गरीब दुनिया में, आजीविका पर दबाव डाला है और भूख और कुपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की धमकी दी है, जिससे अनुकूलन प्रयासों को महत्वपूर्ण बना दिया गया है।
- इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और अन्य साझेदारों के शोधकर्ता छह नीतिगत प्राथमिकताओं की पहचान करते हैं जिन्हें IFPRI की 2022 वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट में अभी लागू किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।
- जलवायु परिवर्तन का खाद्य प्रणालियों पर प्रभाव पड़ता है, और खाद्य प्रणालियाँ भी जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। हाल के अनुमानों के अनुसार, खाद्य प्रणालियाँ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के एक तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं, जिससे उनकी कमी किसी भी शमन प्रयास के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

- वर्तमान में जो धन उपलब्ध है वह अपर्याप्त है। कृषि क्षेत्रों के लिए सरकारी समर्थन, जो वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष $ 600 बिलियन से अधिक है, हानिकारक सब्सिडी और सीमा नियंत्रण को समाप्त करने, हरित नवाचार अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त को पुन: उन्मुख करने, किसानों और अन्य उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
- सुधार व्यक्तिगत और सामूहिक लाभों की स्पष्ट समझ पर आधारित होने चाहिए और व्यापक समर्थन प्राप्त करने और लंबे समय तक चलने के लिए उद्देश्यों, लक्ष्यों और ट्रेड-ऑफ के स्थानीय संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- वनों, महासागरों और मिट्टी में कार्बन सिंक की स्थापना और रखरखाव के माध्यम से, कृषि, वानिकी और अन्य भूमि उपयोग अब एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें शुद्ध उत्सर्जन सिंक बनने की पर्याप्त क्षमता है - जो उत्सर्जन से अधिक जीएचजी को वायुमंडल से बाहर खींचती है।
- जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को पूरा करने के लिए हमारी खाद्य प्रणालियों को पूरी तरह से नया स्वरूप देने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर विधायी परिवर्तन, महत्वपूर्ण निवेश, और एक सक्षम वातावरण की आवश्यकता होगी जो नवाचार को प्रोत्साहित और गले लगाए।
- रिपोर्ट के छह नीतिगत लक्ष्य विकासशील देशों पर केंद्रित हैं, जिनमें से कई पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का खामियाजा भुगतने की संभावना है, लेकिन अनुकूलन और दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली परिवर्तन का समर्थन करने के लिए संसाधनों की कमी है।

- कई मौजूदा तकनीकी नवाचार, जैसे सिंचाई पंपों और कोल्ड स्टोरेज के लिए सौर ऊर्जा, जीनोम-संपादन प्रौद्योगिकियों, और मूल्य श्रृंखला के साथ डिजिटलीकरण, ने उत्पादकता में वृद्धि करते हुए उत्सर्जन को कम करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, भूख और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में जीत के अवसर पेश किए हैं। विभिन्न स्थानीय सेटिंग्स में अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन और अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक धन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
- एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन प्रणालियों में स्थायी संसाधन प्रबंधन में सुधार करने की क्षमता है, लेकिन वे जटिल हैं इसीलिए व्यापक और समावेशी शासन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन को प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को बढ़ावा देना चाहिए, मिट्टी की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए काम करना चाहिए, भूमि के अधिकार को मजबूत करना चाहिए और सभी हितधारकों को स्थिरता में निवेश करने और संसाधन प्रशासन में भाग लेने के लिए पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए।
- एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आहार को स्वस्थ, सस्ता और सुलभ बनाना है। शोध से पता चलता है कि सभी देश राष्ट्रीय खाद्य-आधारित आहार मानकों को लागू करते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के लिए अनुसंधान एवं विकास पर जोर देते हैं और खाद्य पर्यावरण में सुधार का समर्थन करते हैं जो उपभोक्ताओं को स्वस्थ और स्थायी विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- जबकि व्यापार से संबंधित जीएचजी उत्सर्जन को कम किया जाना चाहिए, खुला व्यापार संसाधन दक्षता को प्रोत्साहित करता है और मूल्य श्रृंखला के लिए एक बफर के रूप में कार्य करता है।
- मूल्य श्रृंखलाओं में जलवायु-स्मार्ट तकनीकों में निवेश भी मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और खाद्य हानि और अपशिष्ट को काफी हद तक कम करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक सुरक्षा गरीब लोगों को जोखिमों, विशेष रूप से जलवायु खतरों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अधिक लचीला बनने के लिए अपनी आजीविका में विविधता लाने में सक्षम बनाती है।

प्रारंभिक परीक्षा मे पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

Que. ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की गणना के लिये IFPRI द्वारा उपयोग किये जाने वाले संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा/से है/हैं?

1. अल्पपोषण
2. चाइल्ड स्टंटिंग
3. बाल मृत्यु दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 (b) 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

Ans. (c) केवल 2 और 3

विधि आयोग

समाचार पत्रों में क्यों?

विधि आयोग बिना अध्यक्ष के कार्य कर रहा है। तीन साल की अवधि के लिए गठित आयोग ने पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस चौहान का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त होने के बाद से कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है।

त्वरित मुद्दा?

- सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी, 2020 को किया गया था। हालांकि, नियुक्तियों में आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।
- मूल रूप से 1955 में गठित, आयोग का हर तीन साल में पुनर्गठन किया जाता है और अब तक 277 रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है।
- न्यायमूर्ति बीएस चौहान (सेवानिवृत्त) के तहत पिछले विधि आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव और एक समान नागरिक संहिता जैसे प्रमुख मुद्दों पर रिपोर्ट और कार्य पत्र प्रस्तुत किए थे।
- एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होने के अलावा, आयोग में एक सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
- कानून मंत्रालय में कानून और विधायी सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे।
- इसमें पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य भी नहीं होंगे।
- उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आयोग के अध्यक्ष होंगे।

अन्य प्रमुख तथ्य?

भूमिकाएं और कार्य:

- विधि आयोग, केंद्र सरकार या स्वप्रेरणा द्वारा उसके संदर्भ में, सुधार करने और नए कानून बनाने के लिए भारत में कानून में अनुसंधान और मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा।
- यह प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों के त्वरित निपटान, मुकदमेबाजी की लागत में कमी आदि के लिए न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा मे पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

Que. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 22वें विधि आयोग का गठन सरकार द्वारा फरवरी 2020 में किया गया था।
2. भारत का विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1।
(b) केवल 2
(c) दोनों
(d) कोई भी नहीं

Ans. (c) दोनों